राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (20 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से ऋण सहायता (आईबीआरडी क्रेडिट) के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत "राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना" नामक एक बाहरी सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

लाभ

- एनआरईटीपी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सहायता एवं परियोजना द्वारा सुगम कराये जाने वाले उच्च स्तरीय उपायों से आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा में बढ़ोतरी होगी तथा डिजिटल वित्त एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्य विशेषताएँ

- डीएवाई-एनआरएलएम निर्धनों में से सबसे निर्धन एवं सबसे निर्बल समुदायों को लक्षित करने एवं उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देता है।
- एनआरईटीपी के अंतर्गत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक माध्यमों का मार्गदर्शन करने, ग्रामीण उत्पादों के आसपास मूल्य श्रृंखला सृजित करने, आजीविका संवर्धन में नवोन्मेषी मॉडलों को प्रस्तुत करने एवं डिजिटल वित्त की सुविधा एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।
- डीएवाई-एनआरएलएम पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के बीच परामर्श के लिए आपसी रूप से लाभदायक कामकाजी संबंध और औपचारिक मंच उपलब्ध कराता है।
- एनआरएलएम ने युक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में, जहां एनआरएलएम संस्थान और पीआरआई एक साथ मिल कर काम करेंगे, परस्पर समन्वय को सुगम बनाने के लिए गतिविधि मानचित्र भी विकसित किया है जिसे सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को प्रसारित कर दिया गया है।

रोजगार युक्त गांव

बिजनेस टुडे, (20 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रोजगार युक्त गांव के अंतर्गत निम्नलिखित की मंजूरी दी है।
- वर्तमान योजनाओं बाजार संवर्धन और विकास योजना (एमपीडीए), खादी अनुदान, ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी) और ग्रामोद्योग अनुदान को जारी रखने के लिए सभी को वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 2800 करोड़ रुपये की कुल लागत से 'खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत' सम्मिलित कर लिया जाएगा।
- खादी क्षेत्र में उद्यम आधारित कार्य शुरू करने और वर्तमान तथा अगले वित्त वर्ष (2018-19 और 2019-20) में हजारों नए कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नये संघटक 'रोजगार युक्त गांव' को लाना।

उद्देश्य

- खादी कारीगरों को 10,000 चरखे, 2,000 करघे और 100 ताना-बाना इकाइयां प्रदान करके इसे 50 गांवों में शुरू करना है,

जिससे प्रति गांव 250 कारीगरों को सीधे रोजगार मिल सके।

- 3 साझेदारों – खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) सहायता प्राप्त खादी संस्थान, कारीगरों और व्यवसायी सहयोगियों के बीच साझेदारी के जरिए 'सब्सिडी वाले मॉडल' के स्थान पर उद्यम संचालित बिजनेस मॉडल' शुरू करना।
- ग्रामोद्योग सामान के अंतर्गत कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्कृत शहद, ताड़ का गुड़ आदि, हस्त निर्मित कागज और चमड़ा, मिट्टी के बर्तन और उत्पाद नवोन्मेष के माध्यम से स्वास्थ्य तथा कॉस्मेटिक्स क्षेत्र, डिजाइन विकास और उत्पाद विविधता पर विशेष ध्यान देना।
- प्रति गाँव निवेश की कुल पूंजी सब्सिडी के रूप में 72 लाख रु. और बिजनेस साझेदार से कार्यशील पूंजी के रूप में 64 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

रूफटॉप सोलर कार्यक्रम

द हिन्दू, (20 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर (आरटीएस) परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है।

क्या है?

- इस कार्यक्रम को 11,814 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
- कार्यक्रम के दूसरे चरण में आवासीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का पुनर्गठन किया गया है।
- इसके तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए 40 प्रतिशत सीएफए और 3 किलोवाट से ज्यादा एवं 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए 20 प्रतिशत सीएफए उपलब्ध कराई जाएगी।
- ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरएडब्ल्यू) के मामले में साझा सुविधाओं को विद्युत आपूर्ति हेतु आरटीएस संयंत्रों के लिए सीएफए को 20 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।

- हालांकि, जीएचएस/आरएडब्ल्यू के लिए सीएफए हेतु मान्य क्षमता प्रति मकान 10 किलोवाट तक ही सीमित होगी।
- इसके अंतर्गत अधिकतम कुल क्षमता 500 केडब्ल्यूपी तक होगी, जिसमें जीएचएस/आरएडब्ल्यू के अंतर्गत व्यक्तिगत मकानों में लगाए गए आरटीएस की क्षमता भी शामिल होगी।
- आवासीय श्रेणी के तहत सीएफए 4000 मेगावाट की क्षमता के लिए मुहैया कराई जाएगी और यह मानक (बेंचमार्क) लागत या निविदा लागत, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- केन्द्रीय वित्तीय सहायता अन्य श्रेणियों यथा संस्थागत, शैक्षणिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की ज्यादा सहभागिता पर फोकस किया जाएगा।

लाभ

- इस कार्यक्रम का कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में बचत की दृष्टि से व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा।
- प्रति मेगावाट 1.5 मिलियन यूनिटों के औसत ऊर्जा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2022 तक कार्यक्रम के चरण-2 के तहत 38 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयत्रों की स्थापना से प्रति वर्ष कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 45.6 टन की कमी होगी।
- इस कार्यक्रम के द्वारा स्व-रोजगार को बढ़ावा मिलने के अलावा वर्ष 2022 तक योजना के चरण-2 के अंतर्गत 38 जीडब्ल्यू की क्षमता वृद्धि हेतु कुशल एवं अकुशल कामगारों के लिए 9.39 लाख रोजगारों के समतुल्य रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।

कुसुम योजना

Pib (20 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) का शुभारंभ करने की मंजूरी दे दी।

इसके तीन घटक हैं

- इस योजना के अनुसार बंजर भूमियों पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली में से अधिशेष अंश को किसान ग्रिडों को आपूर्ति कर सकेंगे जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
- इसके लिए, बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को किसानों से पाँच वर्षों तक बिजली खरीदने के लिए 50 पैसे प्रति इकाई की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- सरकार किसानों को खेतों के लिए 5 लाख ऑफ-ग्रिड (ग्रिड रहित) सौर पम्प खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी. केंद्र और राज्य प्रत्येक सौर पम्प पर 30% सब्सिडी प्रदान करेंगे।
- अन्य 30% ऋण के माध्यम से प्राप्त होगा, जबकि 10% लागत किसान द्वारा वहन की जायेगी।
- 7,250 MW क्षमता के ग्रिड से सम्बद्ध (ग्रिड-कनेक्टेड) खेतों के पम्पों का सौरकरण (Solarisation) किया जाएगा।
- सरकारी विभागों के ग्रिड से सम्बद्ध जल पम्पों का सौरकरण किया जाएगा।

अपेक्षित लाभ

- यह कृषि क्षेत्र को डीजल-रहित बनाने में सहायता करेगा. यह क्षेत्रक लगभग 10 लाख डीजल चालित पम्पों का उपयोग करता है।
- यह कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का बोझ कम कर DISCOMs की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सहायता करेगी।
- विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ऑफ-ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड, दोनों प्रकार के सौर जल पम्पों द्वारा सुनिश्चित जल स्रोतों के प्रावधान के माध्यम से किसानों को जल-सुरक्षा।
- नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों का समर्थन करना।
- छतों के ऊपर और बड़े पार्कों के बीच इंटरमीडिएट रेंज में सौर ऊर्जा उत्पादन की रिक्तियों को भरना।

अंतरिक्ष नीति-निर्देश

बिजनेस लाइन, (21 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अन्तरिक्ष सैन्य बल बनाने के लिए अन्तरिक्ष नीति-निर्देश – 4 (Space Policy Directive-4 (SPD-4) नामक आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इस नीति-निर्देश के अनुसार, अमेरिकी रक्षा विभाग सेना की एक अलग शाखा स्थापित करेगा जो वर्तमान में संचालित स्थल, नौ, वायु, सामुद्रिक और तटरक्षक सेनाओं के बाद देश की छठी सेना होगी।
- अभी इस नीति-निर्देश पर अमेरिकी कांग्रेस का अनुमोदन लिया जाना शेष है।

अन्तरिक्ष सैन्य बल

- अमेरिकी अन्तरिक्ष सैन्य बल का मुख्य लक्ष्य अन्तरिक्ष में अमेरिका के वर्चस्व को सुनिश्चित करना है।
- अभी यह अन्तरिक्ष सेना नौसेना के अंदर ही होगी जिस प्रकार सामुद्रिक सेना अमेरिका के नौसेना का एक भाग है।
- अन्तरिक्ष सेना अपने सैनिकों का संगठन करेगी तथा इसके लिए आवश्यक शस्त्र, उपकरण आदि की व्यवस्था करेगी।

क्यों पड़ी जरूरत?

- अन्तरिक्ष सैन्य के जरिए अमेरिका अपने प्रतिद्वंद्वियों चीन और रूस की मंशा पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है।
- 2007 में चीन ने अपने ही उपग्रहों को अन्तरिक्ष में नष्ट कर दिया था। रूस ने भी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसका उपयोग उपग्रहों को ट्रैक और नष्ट करने के लिए किया जा सकता है।
- इसलिए अमेरिका को डर है कि अब ये देश उसके उपग्रहों को भी जब चाहे नष्ट कर सकते हैं इसलिए अमेरिका को अब एक अन्तरिक्ष सैन्य की जरूरत महसूस हो रही है।

समस्याएं

- पहले से चल रही पाँच-पाँच सेनाओं के अलावे एक छठी सेना बनाने से अमेरिकी रक्षा विभाग की संगठनात्मक चुनौतियाँ बढ़ जाएँगी।
- नई सेना को सुदृढ़ करने के प्रयास से अन्तरिक्ष में भेजे जाने वाले असैन्य अभियानों में कटौती करनी पड़ सकती है।

- नई सेना के कारण भविष्य में बजटीय आवंटन बहुत अधिक बढ़ सकता है।
- यद्यपि अन्तरिक्षयानों को ईंधन की खपत की दृष्टि से कम खर्च वाला बनाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन इस काम में अभी भी ऊर्जा की भयंकर आवश्यकता होती है। अन्तरिक्ष सैन्य बल स्थापित हो जाने के बाद इस खर्च में बहुत बड़ा उछाल आएगा।
- अन्तरिक्ष में अधिक से अधिक अन्तरिक्षयान छोड़े जाने के कारण उनका मलबा बढ़ने की भी आशंका है।

मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, 2019

टाइम्स ऑफ इंडिया, (21 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में कैबिनेट ने मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण), द्वितीय अध्यादेश, 2019 जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- संविधान की धारा 123 के खंड (1) के अंतर्गत एक अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव, जिसका नाम मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण), द्वितीय अध्यादेश, 2019 है।
- इसका उद्देश्य मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2018 जो राज्यसभा में लंबित है, में आवश्यक आधिकारिक संशोधन करना है, जिससे कि उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर प्रारूपण एवं अनुवर्ती प्रकृति के ऐसे संशोधनों को रखा जा सके, जिसे आवश्यक माना जा सकता है।

लाभ

- प्रस्तावित अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा एवं उन्हें उनके पतियों द्वारा तत्कालिक एवं अपरिवर्तनीय 'तलाक-ए-बिद्दत' के प्रचलन के द्वारा तलाक दिए जाने को रोकेगा।
- यह तीन तलाक यानी 'तलाक-ए-बिद्दत' की प्रथा को निरुत्साहित करेगा। प्रस्तावित अध्यादेश का प्रख्यापन आजीविका भत्ता, तीन तलाक यानी 'तलाक-ए-बिद्दत' के पीड़ितों के नाबालिग बच्चों को संरक्षण का अधिकार प्रदान करेगा।

तीन तलाक क्या है?

- इस्लाम में तलाक के तीन प्रकार हैं- अहसान, हसन और तलाके बिद्दत (Teen Talaq)।
- इनमें से अहसान और हसन तलाक वापस ली जा सकती है, परन्तु तलाक-ए-बिद्दत वापस नहीं होती है।
- तलाक-ए-बिद्दत 20 से अधिक मुसलमानी देशों, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित, में प्रतिबंधित हो चुका है।

सिकारिया मेगा फूड पार्क

इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, (21 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ने त्रिपुरा राज्य के सबसे बड़े मेगा फूड पार्क, सिकारिया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। यह त्रिपुरा राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है।

क्या है?

- मेगा फूड पार्क योजना भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यवसायियों को एक मंच पर लाकर ऐसी सुविधा देना है जिससे कृषि उत्पादन से लेकर बाजार तक का सम्पर्क सुचारू हो सके।
- इस प्रकार का पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार अधिकतम 50 करोड़ रुपये का अनुदान देती है पर इसके लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जो अलग-थलग होकर एक ही स्थान पर हो। सरकार द्वारा परियोजना की सम्पूर्ण लागत का 50% दिया जाता है।

संचालन प्रक्रिया

- यह परियोजना धुरी और तीलियाँ मॉडल पर आधारित है। इसमें खेत के पास एक अवसंरचना तैयार की जाती है जहाँ प्राथमिक प्रसंस्करण तथा भंडारण होगा।
- इन अवसंरचनाओं को प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (PPCs) तथा संग्रहण केंद्र (CCs) का नाम दिया गया है। इनके अतिरिक्त एक केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (CPC) भी होगा।

- इन प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों का काम उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना होगा, जिससे केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों (CPCs) को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति होती रहे।
- केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र में प्रसंस्करण की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यहाँ पर स्थित इकाइयाँ खाद्य प्रसंस्करण का कार्य करेंगी। इस केंद्र के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है।
- यह योजना माँग के अनुसार चलने वाली योजना है और इसका एक काम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर पर्यावरण, सुरक्षा एवं सामाजिक मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी है।

लोफार दूरबीन

द हिन्दू, (21 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में रात्रिकालीन आकाश का एक नया नक्शा प्रकाशित किया गया है।
- इसमें अन्य दृष्टि-उपकरणों से पता नहीं लगने वाले प्रकाश स्रोतों को पकड़ने की क्षमता रखने वाली लोफार दूरबीन (LOFAR telescope) का प्रयोग कर लाखों ऐसी आकाशगंगाओं का पता लगाया गया है जिनसे हम पहले अनजान थे।
- इस खोज से ब्रह्मांड के कुछ गहनतम रहस्य प्रकट होते हैं, जैसे – कृष्ण विवरों (black holes) की बनावट और आकाशगंगाओं के संकुलों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया।

क्या है?

- इसका पूरा नाम है – Low-Frequency Array
- यह बहुत बड़ा रेडियो दूरबीनों का जाल है जो मुख्य रूप से नीदरलैंड में अवस्थित है।
- इसे नीदरलैंड्स इंस्टिट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी (ASTRON) ने अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर 2012 में पूरा किया था।

कार्य?

- इसमें में कई दिशाओं वाले एंटेना होते हैं। इसमें अलग-अलग एंटेना के संकेतों को क्षण-प्रतिक्षण संयोजित नहीं किया जाता है जैसा कि अधिकांश कई एंटेना वाली दूरबीनों में होता है।
- लोफार के एंटेनों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को डिजिट में लाकर उन्हें एक केन्द्रीय डिजिटल प्रोसेसर तक ले जाया जाता है और फिर सॉफ्टवेयर में संयोजित कर दिया जाता है जिससे कि वे पारम्परिक अन्टेना जैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकें।
- लोफार में लगभग 20,000 छोटे-छोटे एंटेना कम से कम 48 केन्द्रों पर काम करते हैं।
- लोफार ब्रह्मांड का नक्शा 10–240 MHz की रेडियो बारंबारता पर तैयार करता है जिससे चित्र बहुत अधिक साफ और संवेदनशील निकलते हैं।

स्टार्ट-अप रैंकिंग

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (21 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने स्टार्ट-अप से जुड़ी पहलों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण का अनावरण किया।

रैंकिंग 2019 की रुपरेखा

- रैंकिंग रूपरेखा (फ्रेमवर्क) 2019 में 7 आधार और 30 कार्य-बिंदु शामिल हैं।
- इन आधारों के जरिए संस्थागत सहायता, नियम-कायदों को सरल करने, सार्वजनिक खरीद को आसान करने, इन्क्यूबेशन संबंधी सहयोग, प्रारंभिक पूंजी के वित्त पोषण संबंधी सहयोग, उद्यम वित्त पोषण संबंधी सहायता एवं जागरूकता और पहुंच संबंधी गतिविधियों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन किया जाता है।
- रैंकिंग से जुड़ी इस कवायद का उद्देश्य 1 मई, 2018 से लेकर 30 जून, 2019 तक की आकलन अवधि के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जाने वाले उपायों का आकलन करना है।
- विभाग ने रैंकिंग रूपरेखा के 7 आधारों से जुड़े उल्लेखनीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है।
- रैंकिंग 2019 कवायद के एक हिस्से के रूप में डीपीआईआईटी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अभिनव स्टार्ट-अप कार्यक्रमों और पहलों को मान्यता प्रदान करेगा।

उद्देश्य

- स्टार्ट-अप को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की सुदृढ़ व्यवस्था करने की दृष्टि से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है।
- इस रूपरेखा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एक-दूसरे की अच्छी प्रथाओं या तौर-तरीकों की पहचान करें, उनसे सीखें और उन्हें अपने यहां अमल में लाएं।

पृष्ठभूमि

- औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग जनवरी, 2016 से राज्यों में स्टार्ट-अप से सम्बंधित पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा करता आया है।
- इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य था राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों को अपने यहाँ स्टार्ट-अप से सम्बंधित पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बढ़ कर कदम उठाने हेतु प्रोत्साहन देना। इसके लिए क्षमता विकास पर विशेष बल दिया गया।
- इसका एक अन्य उद्देश्य देश में सहयोगात्मक संघीयता की भावना को आगे बढ़ाना भी है।
- इसके लिए जिन तरीकों को अपनाया गया है, उनका लक्ष्य है राज्यों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना और उन्हें अच्छी-अच्छी प्रथाओं को सीखने, अपनाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसकी शुरूआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत की गयी है।
2. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, निर्धनों में से सबसे निर्धन एवं निर्बल समुदायों को लक्षित करने तथा उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत रोजगार युक्त गांव की अवधारणा लायी गयी है।
2. ग्रामोद्योग सामान के अंतर्गत केवल कृषि आधारित उद्योग को शामिल किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

3. 'रूफटॉप सोलर कार्यक्रम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत वितरण कंपनियों की अधिक सहभागिता पर बल दिया जाएगा।
2. हाल ही में इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में 2022 तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

4. 'कुसुम योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारम्भ किया गया है।
2. यह योजना महिलाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतरिक्ष नीति निर्देश के अनुसार अंतरिक्ष सैन्य बल अमेरिकी रक्षा विभाग की छठी सेना होगी।
2. अभी अंतरिक्ष सैन्य बल अमेरिकी नौसेना के अंतर्गत कार्यरत रहेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में कैबिनेट ने मुस्लिम (विवाह के अधिकार का संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, 2018 जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
2. यह प्रस्तावित अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा और 'तलाक-ए-बिद्दत' की प्रथा को रोकेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मेगा फूड पार्क योजना भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
2. सिकारिया मेगा फूड पार्क अरुणाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

GS World Committed To Excellence

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

8. 'लोफार दूरबीन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह बहुत बड़ा रेडियों दूरबीनों का जाल है जो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है।
2. इसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ग्लोनॉस द्वारा 2012 में बनाया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्ट-अप से जुड़ी पहलों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण का अनावरण किया है।
2. रैंकिंग रूपरेखा 2019 में 7 आधार और 30 कार्य बिंदु शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

नोट : 16-19 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(c), 4(c), 5(b), 6(c), 7(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence